

पीओके हमारा है...जम्मू—कश्मीर पर अमित शाह ने कहा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित

नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर पर लोकसभा में मंजूरी के लिए लागू गए दो विधेयक उन लोगों को अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं जिन्होंने अन्याय का सामना किया और अपमानित और नजरअंदाज किए गए। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए सहानुभूति जताई।

पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है...

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि दड़ड हमारय है और साथ का साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रतिष्ठित कश्मीरी याद रखेगा कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बहस का



अधिकार प्रदान करना

उन्होंने कहा, "जो विधेयक मैं यहां लाया हूँ वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनके अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान किया गया और जिनकी उपाधी को गंवाया। किसी भी समाज में, जो वंचित है उन्हें आगे लाना चाहिए। यही मूल बात है भारत के संविधान की। लेकिन उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मानपूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।

"प्रधानमंत्री गरीबों का दर्द जानते हैं" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने इस विधेयक को कम आंकने की भी कोशिश की। किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो हमें देखना होगा कि नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है।

मुख्य सचिव ने की पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा



देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संघु ने बुधवार को सचिवालय में पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिव स्तर पर सप्ताह में 2 बार बैठक कर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने

कहा कि प्रस्तावों के अनुमोदन के लिये डेडलाइन्स टाईम लगाई जाए ताकि फाइलों के पारगमन में अत्यधिक समय न लगे। मुख्य सचिव ने प्रदेश में पुस्तकालयों के निर्माण पर अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पुस्तकालयों को मजबूत किया जाए। साथ ही जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ नए तैयार किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों का लाभ स्थानीय लोग भी उठा सकें इसके लिए पुस्तकालय की एंटी विद्यालय के बाहर से दी जाए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी भूमि के उपयोग के लिये अगले 30 से 50 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग अगले 50 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से मास्टर प्लान बना लेंगे तो भूमि का उचित रूप से उपयोग हो सकेगा। इससे विभागों की भविष्य की आवश्यकताओं को सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिये। कहा कि जिन विभागों का बजट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, विभाग तेजी से कार्यों को पूरा कर उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएँ।

अब सुप्रीम कोर्ट में वनंतरा प्रकरण पर फरवरी में होगी सुनवाई



नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल की बेटी की ऋषिकेश के समीप वनतरा रिसॉर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुरोध पर अगली सुनवाई फरवरी माह तक के लिए स्थगित कर दी।

इस मामले में उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने बताया कि इस मामले में इसमें कुछ राजनीतिक वीआईपी की संलिप्तता का आरोप झूठा और राजनीति से प्रेरित है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की संयुक्त पीठ में पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी आशुतोष नेगी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई हुई। जिसमें इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।

प्रेमी ने रिसॉर्ट में कथित वीआईपी से की थी मुलाकात

नैनीताल। हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका के खारिज होने के बाद नेगी ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी। सुनवाई के दौरान गन्ध सरकार की ओर से पेश उप महाधिवक्ता खंडपीठ को बताया कि राजनीतिक वीआईपी के संबंध में याचिकाकर्ताओं की एसएलपी से पता चला है कि प्रेमी ने रिसॉर्ट में कथित वीआईपी से मुलाकात की थी लेकिन वह व्यक्ति वीआईपी नहीं था।

कोर्ट में गवाह के तौर पर उनका बयान दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वीआईपी के शामिल होने

भारतीय तीर्थयात्रियों की हज और उमरा यात्रा होगी और भी सुविधाजनक



नई दिल्ली। मक्का की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सज्दी अब अधिक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

सज्दी के हज और उमरा मंत्री तौफिक बिन फोजान अल-रबिया ने बुधवार को बताया कि ये पहल विशेष रूप से भारतीय तीर्थयात्रियों के यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे विशेष रूप से स्वतंत्र उमरा यात्राओं पर जाने वाली महिलाओं को लाभ होगा। उमरा वीजा को 90 दिनों तक बढ़ाने के साथ-साथ 4 दिन के ट्रांजिट वीजा को भी शुरू किया जा रहा है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

बात करते हुए अल-रबिया ने कहा, 'लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर इसका उद्देश्य सभी यात्रियों के लिए अधिक पूर्ण और सुरक्षित तीर्थयात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।

पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 100 वेबसाइट बंद

नई दिल्ली। "घर बैठे नौकरी" और "घर बैठे कमाई" का झांसा देकर आम लोगों को चूना लगाने वाले 100 वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है। गृहमंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी) ने इन वेबसाइटों की पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, उसके बाद सूचना व प्राथमिकी मंत्रालय ने इन्हें बंद कर दिया।

गृहमंत्रालय के अनुसार ये वेबसाइट विदेशी धरती से चलाए जा रहे थे और भारतीयों के साथ धोखाधड़ी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गए थे। इनके विज्ञापन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में किये जा रहे थे। गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देने वाले विज्ञापनों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों, महिलाओं और काम की तलाश कर रहे युवाओं को जाल में फंसाना होता है।

पीएनबी घोटाले मामले में एक आरोपी को पांच साल की सजा



रुड़की। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए लाखों रुपये की गड़बड़ी के मामले में एक एजेंट को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर विभिन्न धाराओं में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक आरोपित एजेंट के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 जून 2022 को पंजाब नेशनल बैंक के

ऐसे खुला घोटाले का राज

इस बात पर लोगों ने ही बताया कि गांव का ही रहने वाला बैंक एजेंट जाबिर एवं पूर्व प्रबंधक ऋचा पंवार ने पूर्व में ऐसी स्कीम में लोगों का पैसा लगाया है। इसके बाद बैंक पर हंगामा भी हुआ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले में पहले तो जाबिर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस साल 19 मई को पूर्व बैंक प्रबंधक ऋचा पंवार को भी पुलिस ने मंगलौर से गिरफ्तार कर लिया था।

सुनाई गई पांच साल की सजा

सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्रिधा रावत की अदालत में 28 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित जाबिर को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर विभिन्न धाराओं के तहत 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। आरोपित वर्तमान में जेल में बंद है।

उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड में शामिल हुए मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड में शामिल होकर रैतिक परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान राष्ट्रसेवा का अद्वितीय उदाहरण हैं। रैतिक परेड में जवानों द्वारा मोटरबाइक पर साहस, कौशल एवं सन्तुलन के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जवान हमारे सहयोगी हैं, और विभिन्न नागरिक सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में उनका योगदान रहता है। होमगार्ड्स के जवानों को कड़ी धूप सहित बरसात और कड़कड़ाती ठंड में यातायात एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर करते हुए उन्होंने देखा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि होमगार्ड्स विभाग में शत्रु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु इण्डोर फायरिंग रेंज को प्रेमनगर में उपलब्ध विभागीय भूमि पर निर्माण किया जायेगा। होमगार्ड्स जवानों को वर्ष भर में 12 आकस्मिक अवकाश दिये जायेंगे। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की कम्पनी कार्यालय/ट्रांजिट कैम्प/इमरजेंसी सच एवं रेस्क्यू सेंटर



हेतु भवन निर्माण किया जाएगा। विभागीय मोटर साइकिल दस्ते हेतु मोटर साइकिल त्रय की जाएंगी। पुलिस कार्मिकों एवं एन०डी०आर०एफ० की भांति उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोविड महामारी हो, कोई

वीआईपी कार्यक्रम हो या फिर कांवेड या अन्य बड़े आयोजन, होमगार्ड्स जवान जिस निष्काम सेवा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो अभूतपूर्व है। होमगार्ड्स जवानों का एक ही मंत्र रहा है, जहाँ कम वहाँ हम इसी संकल्प के साथ, प्रदेश के विकास में भी अपनी भागेदारी निभा रहे हैं।

IHMS

KOTDWAR

Institute of Hospitality, Management & Sciences

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Sri Dev Suman Uttarakhand University, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University (A Central University)

Approved By: All India Council of Technical Education (AICTE), Government of Uttarakhand and Ministry of Education

17 Year of Excellence in Education
ESTD. 2006

"Journey Towards Excellence"

Admissions Open 2024-25

LIMITED SEATS

CHM

(CERTIFICATE IN HOTEL MANAGEMENT)

JOB OPPORTUNITIES

PROGRAMMES AVAILABLE

M.B.A.	M.C.A.	B.H.M.	B.B.A.	B.C.A.	B.Sc. IT	C.H.M.
2 Years	2 Years	4 Years	3 Years	3 Years	3 Years	1 Year

Mob.: 7902000023, 8057726863

Balbhadrapur, B.E.L. Road, Kotdwar-246149(UK)

Email:Info@ihms.ac.in, ihmskotdwar1@gmail.com | Web: www.ihms.ac.in



उत्तराखण्ड में असीम संभावनाओं का अनावरण आपकी समृद्धि का प्रवेश द्वार



“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हट संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड की आर्थिकी और पर्यटन विकास में वृद्धि हुई है। हमारा राज्य व्यापार के लिये सदैव खुला है, जो निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान करता है। सुव्यवस्थित उद्योग की मंजूरी से लेकर निवेशकों को प्रोत्साहित करने तक हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्यमों के लिये एक सम्पन्न पाठ्यस्थितिकी तंत्र का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। आइये मिलकर उत्तराखण्ड के भविष्य को नया आकार प्रदान करें!

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

IT/ITeS Policy 2023

पात्र परियोजनाएँ/परियोजनाओं के प्रकार

- निम्नलिखित निवेश सीमाओं के साथ आईटी इकाइयाँ/आईटी परिसर/जीसीसी:
- मैदानी क्षेत्र - ईसीए में 9 वर्षों के भीतर 100 करोड़ से अधिक का निवेश और 1,000 कर्मियों का न्यूनतम स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार
- पर्वतीय - ईसीए में 9 वर्षों के भीतर 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और 500 कर्मियों का न्यूनतम स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार

प्रोत्साहन विवरण

- प्रतिबद्ध निवेश के 25% तक कैपेक्स सब्सिडी या
- सरकारी भूमि बैंक से भूमि का आवंटन या
- सरकारी भूमि बैंक से भूमि का आवंटन + कैपेक्स सब्सिडी का संयोजन (प्रतिबद्ध निवेश के 25% तक सीमित)

संस्थागत समर्थन

- सिगल विंडो सिस्टम
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- निवेशक सुविधा केंद्र
- सरकारी भूमि बैंक से भूमि आवंटन

प्रदेश की समृद्धि में भागीदार बनें



अधिक जानकारी के लिए
investuttarakhand.uk.gov.in
पर लॉग ऑन करें

टोल फ्री
18003097225

[/ukgis2023](https://www.facebook.com/ukgis2023)



Pumped Storage Policy 2023

पात्र परियोजनाएँ/परियोजनाओं के प्रकार

- पम्प भंडारण नीति के तहत पम्प स्टोरेज उत्पादों को सहायता प्रदान जायेगी:
- ऑन-स्ट्रीम परियोजनाएँ - नदी की धारा पर स्थित कम से कम एक भंडारण
 - ऑफ-स्ट्रीम परियोजनाएँ - नदी की धारा पर कोई भंडारण स्थित नहीं

नीति में दिये गए दिशानिर्देशों के आधार पर उपरोक्त श्रेणी की परियोजनाएँ आवंटित की जायेगी।

प्रोत्साहन विवरण

- छूट**
- पीएसपी डेवलपर्स को परियोजना सीओडी से 5 साल की अवधि के लिए इंस्टॉलमेंट ट्रांसमिशन शुल्क का 50% से अधिक बिल नहीं दिया जाना है। शर्तों के अनुसार परियोजना सीओडी वित्तीय वर्ष 2033-34 के पहले पूर्ण हो।
 - स्थानीय क्षेत्र विकास निधि उन परियोजनाओं के लिए ऑफ-स्ट्रीम पीएसपी पर लागू नहीं होगी जहां बिजली राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाती है।
 - राज्य सरकार, पम्प भंडारण परियोजनाओं से कोई भी मुफ्त टॉयल्टी बिजली एकत्र नहीं करेगी।
 - जल कर केवल भंडारण स्थलों में पानी के शुद्ध प्रवेश पर लागू होता है, बिजली उत्पादन के लिए भंडारण स्थलों के बीच पानी के पुनर्चक्रण पर कर लागू नहीं होगा।

भूमि

- निजी भूमि पर स्थानांतरण / निस्तारण की अनुमति आवेदन के 8 सप्ताह के भीतर दी जाएगी।

संस्थागत समर्थन

- राज्य सरकार इस नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी और ऊर्जा सेल द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

Drone Policy 2023

पात्र परियोजनाएँ

- ड्रोन सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण (डीएसडीएम) उद्यम
- ड्रोन सक्षम सेवाएँ (डीएसएम) उद्यम।

डीएसडीएम और डीएसएम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सब्सिडी,** डीपीआर तैयार करने के लिए भुगतान की गई लागत के 50% की प्रतिपूर्ति, तकनीकी/सिविल कार्यों/प्लॉट और मशीनरी निवेश में प्रमाणन के साथ अधिकतम सीमा 5 लाख
- गैट-मनोरंजक ड्रोन-उपयोग प्रोत्साहन** गैट-मनोरंजन / गैट-पर्यटन ड्रोन उपयोग या सेवाओं में शामिल डीएसएम उद्यम प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे - विशुद्ध एसजीएसटी भुगतान + नकद प्रोत्साहन, भुगतान किए गए विशुद्ध एसजीएसटी की राशि के बराबर।
- सरकारी विभागों द्वारा पायलट परियोजनाओं के लिए समर्थन** पायलट कार्यक्रमों के लिए धन की आसान उपलब्धता के लिए राज्य सरकार एक कोष बनाएगी।
- लीज टैरल के लिए सब्सिडी** आईटीडीए अपने स्वयं के भवनों और कार्यालयों में डीएसडीएम और डीएसएम उद्यमों को ऐसे भवनों और कार्यालयों में अधिसूचित दरों से 50% छूट पर कार्य स्थान प्रदान करेगा।
- गैट-आईटीडीए के लिए भी लीज किराये का प्रावधान**
- राज्य सरकार द्वारा निर्मित 200 करोड़ रुपये के स्टार्टअप वेंचर फंड में 15% ड्रोन हेतु।**
- स्थानीय उद्यम को प्राथमिकता** ड्रोन की खरीद के लिए, सार्वजनिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ड्रोन-घटक और ड्रोन सक्षम सेवाएँ

क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहन

- ड्रोन सीओडी के लिए कैपेक्स सब्सिडी ड्रोन सीओडी के लिए आईटीआई की स्थापना/नवीनीकरण करने वाले निजी उद्यमों को कैपेक्स सब्सिडी
- ड्रोन कार्यक्रम शुरू करने/ड्रोन स्कूल/आरपीटीओ स्थापित करने के लिए सब्सिडी, ऐसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए ड्रोन-उपकरण और ड्रोन-संबंधित सॉफ्टवेयर लागत पर 50% की कैपेक्स सब्सिडी, प्रति संस्थान। करोड़ रुपये की सीमा के अधीन।

अनुकूलित प्रोत्साहन

अनुकूलित पैकेज नीति के तहत लाभ उन ड्रोन निर्माताओं के लिए उपलब्ध है जो न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश करते हैं या संचालन के पहले वर्ष से 250 लोगों या अधिक का प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करते हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023

8-9 दिसंबर 2023
वन अनुसंधान संस्थान (FRI), देहरादून

स्वयं सेवियों ने दिया स्वच्छता का संदेश

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : राजकीय स्वातंत्र्य महाविद्यालय थलीसिंग में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नमामि गंगे के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय नियमित शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रेनु रानी बंसल की अध्यक्षता में किया गया शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत द्वारा किया गया। इस दौरान स्वयं सेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस शिविर में स्वयं सेवियों द्वारा सबसे पहले महाविद्यालय प्रांगण के आसपास कटीली झाड़ियों को साफ किया गया और मुख्य द्वार के अंदर की तरफ से खरपतवार को हटाया गया व पौधों को पानी दिया गया। स्वयं सेवियों द्वारा महाविद्यालय के समीप जल स्रोत के आसपास फेले कचरे को इकट्ठा करते हुए एक स्थान पर ढेर लगाने के पश्चात उसका निस्तारण किया गया। शिविर का संयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विवेक रावत ने किया। शिविर में शिक्षणकर्ता कर्मचारी धर्म सिंह, सुशांत धरमान ने सहयोग दिया।

तुषार श्रीदेव सुमन विवि की वॉलीबाल टीम में चयनित

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की वॉलीबाल टीम को नर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में भेजे जाने के लिए टीम का चयन हुआ है। इस टीम में राजकीय महाविद्यालय नैनीताल के बीए तृतीय वर्ष के छात्र तुषार नेगी को टीम में चुना गया है। प्राचार्य डॉ. बीपी उनियाल ने बताया कि 12 मुख्य खिलाड़ियों में तुषार नेगी का चयन हुआ है। कुश्नेत्र विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 11 दिसंबर को टीम कुश्नेत्र के लिए रवाना होगी। तुषार नेगी का चयन होने पर प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं ने खुशी जताई है।

विधायक ने किया मोटर मार्ग का शिलान्यास

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : शंकरपुर-हल्द्वाल मोटरमार्ग पर ग्राम पंचायत कमेटी के तहत भूंड से कर्मदा तक मोटर मार्ग निर्माण का शिलान्यास विधायक दिलीप रावत ने किया। अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत लोनिवि लैंसडन द्वारा सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क निर्माण से ग्राम पंचायत मुख्यालय कमेटी शंकरपुर हल्द्वाल मोटर मार्ग से जुड़ जाएगा। क्षेत्र के लोगों ने लैंसडन विधायक दिलीप रावत का फूल माला से स्वागत किया व सड़क सुविधा के लिए उनका आभार जताया।

क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण की उठाई मांग

श्रीनगर गढ़वाल : नगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर प्रगतिशील जन मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने मांगों पर शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। सीएम को भेजे ज्ञापन में प्रजम के अध्यक्ष अनिल स्वामी ने कहा कि श्रीनगर एक मात्र उच्च शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित होता शहर है और यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव भी है। उन्होंने श्रीनगर उप जिला चिकित्सालय में पार्किंग बनाये जाने, एनआईटी के स्थाई परिसर निर्माण में आ रही प्रशासनिक अड़चनों का निस्तारण कर अविरोध निर्माण कार्य प्रारंभ करने, श्रीनगर परिवहन डिपो को मुख्य शहर स्थित डिपो स्थल से संचालित किये जाने, श्रीनगर नगर निगम अन्नगत सड़कों के डामरीकरण, सीवर लाइन निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू किये जाने की मांग की है। (एजेंसी)

स्व. भगवान सिंह के नाम पर रखा जाय महाविद्यालय का नाम

श्रीनगर गढ़वाल : राजकीय महाविद्यालय नैखरी का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भगवान सिंह के नाम पर रखे जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग ने उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारी सोनिया पंत के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया।

जयन्त संस्थापक

स्व. नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक, मुद्रक और स्वामी

नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बदीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित

—सम्पादक

नागेन्द्र उनियाल

आर.एन.आई. 35469/79

फोन/फैक्स 01382-222383

मो. 8445596074, 9412081969

e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com